सड़कों पर वीआईपी आतंकवाद का एक अनुभव

फ़रीदाबाद (म.मो.) सुप्रीम कोर्ट के बार-बार मना करने के बावजूद वीआईपी सुरक्षा के नाम पर सड़कों पर काफ़िले बना कर सायरन की भयावह आवाज़ से दहशत पैदा करते हुए चलते हैं। इतना ही नहीं इस काफ़िले में चलने वाली पुलिस की गाड़ियों में सवार बन्दूकची अपनी बंदूकें दिखा-दिखा कर अन्य राहगीरों में बेवजह की दहशत पैदा करते हैं। इस दहशत को अनुभव करने का मौका इस संवाददाता को भी दिनांक 3 जुलाई (शुक्रवार) को चंडीगढ से फ़रीदाबाद लौटते हुए मिला।

रात के करीब साढे आठ बजे शाहबाद व करनाल के बीच न जाने कौन वीआईपी लाल बत्ती की गाड़ी में दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके आगे एक पायलेट गाड़ी और पीछे दो एस्कॉर्ट गाड़ियों में सशस्त्र जवान बैठे थे। कार की लाइट में इससे अधिक कुछ नहीं दिख पा रहा था। पीछे चलती एस्कॉर्ट गाड़ियों की बदमाशी यह थी कि एक तो वीआईपी कार के एकदम पीछे तो दूसरी थोड़ा साइड में होकर इस तरह चल रही थी कि कोई अन्य वाहन उनसे आगे न निकल सके। इसके चलते दर्जनों कारें इनके पीछे एकत्र होती चली गयीं। जो कोई आगे निकलने का प्रयास करे उसे पीछे बैठे जवान बन्दूक से डराते और ड्राइवर गाड़ी को साइड में करके रास्ता रोक लेता। इस गुंडागर्दी से निपटने का जोखिम उठाते हुए, जैसे-तैसे हमने अपनी गाड़ी उनसे आगे निकाली तो हमारे पीछे-पीछे और भी कई गाड़ियां निकल पड़ी।

करनाल ज़िले की सीमा पर दो और पुलिस जिप्सियां इस वीआईपी काफ़िले में जुड़ने को तैयार खड़ी थी। इनके जुड़ने पर कुरूक्षेत्र पुलिस की जिप्सयों को हट जाना था। यही नियम चला आ रहा है। हर ज़िले की सीमा में प्रवेश करते ही वीआईपी की सुरक्षा का नाटक उस ज़िले की पुलिस को करना होता है। ये जिप्सियां प्राय: पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम की होती हैं। केन्द्र सरकार की एक विशेष योजना एवं बजट के तहत लोग़ों की पुकार पर त्वरित कार्यवाही के लिये पीसीआर जिप्सियों की व्यवस्था की गयी थी। जाहिर है जब ये गाड़ियां इस तरह की वीआईपी नाटकबाज़ियों में ही व्यस्त रहेंगी तो ये कैसी त्वरित कार्यवाही कर पायेंगी, समझना मुश्किल नहीं।

पानीपत के करीब पहुंचे तो एक और वीआईपी कार के दर्शन हो गये। नारंगी बत्ती लगी इस कार के आगे-पीछे आतंक फैलाने वाली पुलिस जिप्सियां तो नहीं थीं; परन्तु इस सारे काम को भी यह गाड़ी खुद ही कर लेना चाहती थी। पीछे वाले वाहन का रास्ता रोकना यदि कोई आगे निकल जाय तो सायरन बजा कर पीछा करना और आगे निकल जाना। थोड़ी देर बाद खुद ही गति को घटा देना। ऐसे में फ़िर कोई आगे निकले तो फ़िर झुंझलाहट प्रगट करते हुए सायरेन कार दुरूपयोग करना।

यह तमाशा दिल्ली के मुकरबा चौक तक चला। रात के ग्यारह बज चुके थे। वहां यह गाड़ी साइड में लग कर खड़ी हो गयी। खड़ी गाड़ी को गौड़ से देखा तो वह शायद होंडा सिटी थी जिसका पंजीकरण नम्बर एच आर 51 ए ए-0006 था। अथार्टी से पता चला कि यह गाड़ी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के नाम पर पंजीकृत है। इस तरह की गाड़ी प्राय: डीआईजी अथवा इससे ऊपर के अधिकारी के पास रहती है। परन्तु गाड़ी पर न तो कोई झंडी थी और न ही स्टार। इससे लगता है कि कोई कनिष्ठ कर्मचारी इसे लिये घूम रहे थे।

मुख्यमंत्री खट्टर बेशक बस में यात्रा करते रहें, परन्तु जब तक अन्य मन्त्रियों व सरकारी मशीनरी की लगाम नहीं खींचेंगे, कोई लाभ होने वाला नहीं। फ़रीदाबाद के सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल कल तक यानी सांसद बनने से पूर्व यहां अकेले बेखौफ़ घूमते थे। लेकिन मन्त्री बनते ही वे इतने भयभीत रहने लगे हैं कि एक सुरक्षा जिप्सी स्थाईतौर पर तथा एक अतिरिक्त जिप्सी जिस क्षेत्र में जाते हैं। वहां की साथ लग लेती है। दरअसल सुरक्षा का तो बहाना है। यह सब तो अपना रूतबा दिखाने का तरीका है।

अभी तक यहां के तमाम विधायक बड़े आराम से एक गनमैन लेकर घूम रहे हैं, विधायक बनने से पहले वह भी नहीं था। हां यदि बिल्ली भागों छींका टूट गया और कोई मन्त्री बन गया, फ़िर इन्हें भी पुराने कांग्रेसी मंत्रियों शिवचरण शर्मा व शारदा राठौर की तरह आगे-पीछे पुलिस जिप्सियों की दरकार होगी। यदि यह सब न करें तो फ़िर मन्त्री बनने का फ़ायदा क्या हुआ?

यह है कि ऐसे सुरक्षा काफ़िलों में चलने वाले और ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। क्योंकि अंधेरे में घात लगा कर बैठे हमलावर को दूर से ही इनका आना और काफ़िले में इनका निश्चित स्थान गाड़ी पर लगी लाल बत्ती बता देती है।

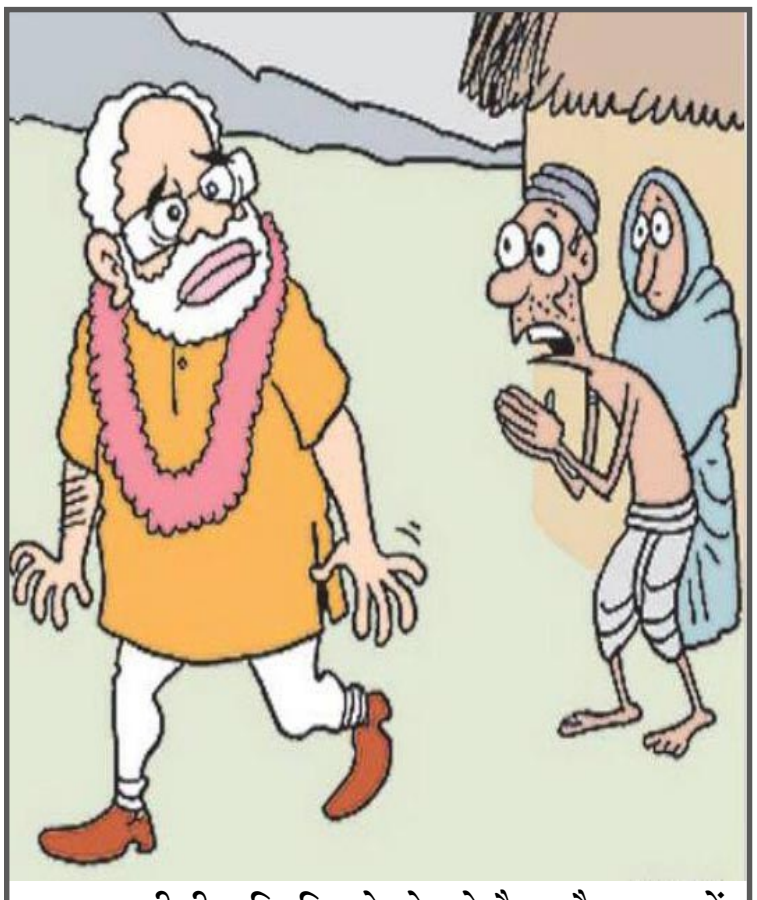

हम एलपीजी सब्सिडि छोडने को तैयार है, बस हमें पार्लियमैंट कैन्टीन में रोटी खाने की छूट दे दो।

पुलिसकर्मी लूट कर खाना अपना अधिकार समझते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 9 जुलाई को तिकोना पार्क आटो मार्केट के मिस्त्रीयों ने इस संवाददाता को वे 3 रेवड़ियां साक्षात दिखाईं जिनसे कुछ देर पहले ही सरकारी बाइक पर सवार दो पुलिस कांस्टेबल चिकन बिरयानी व कचौड़ियां ले गये थे और अक्सर ले जाते रहते हैं। इसकी सूचना एसएचओ कोतवाली को दी गयी तो उन्होंने 2 नम्बर चौकी में पहुंचकर तुरन्त उन लुटेरों को जा दबोचा। सिपाहियों ने अपनी कारगुजारी स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी और भविष्य में इसे न दोहराने की कसम खाई।

माना जा सकता है कि एसएचओ के धमकाने समझाने से वे सिपाही समझ गये हैं भविष्य में इस तरह से पुलिस की वर्दी को अपमानित नहीं करेंगे। परंतु समझने वाली बात तो यह है कि उन बड़े अफ़सरों को कौन समझाये। जिनको देख कर ये नये-नये सिपाही इस तरह की हरकतें करना सीखते हैं। 'मज़दूर मोर्चा' के 16-30 नवम्बर 2014 अंक में एसएचओ सेक्टर 7: नाम भिखारी काम डकैती के शीर्षक से खबर प्रकाशित की गयी थी। इसमें दर्शाया गया था कि एसएचओ विष्णु प्रसाद किस प्रकार से अपने ड्राइवर (सिपाही) को सरकारी गाड़ी में भेज कर अपने इलाके में लगने वाली शब्ज़ी मंडी के विक्रेताओं से शब्ज़ी इकट्ठी करवाता था। दो-चार बार तो ड्राइवर ने यह ज़लील काम किया, लेकिन जब उसे बहुत शर्म आने लगी तो उसने साफ़ मना कर दिया। लेकिन वह एसएचओ पक्का बेशर्म था। ड्राइवर के मना करने पर खुद सरकारी गाड़ी लेकर शब्ज़ी एकत्र करने लगा। इसी तरह अपने इलाके के ढाबों व हलवाइयों से भी खाने-पीने का सामान एकत्र करता था

ऐसे ही अनेकों काले कारनामे उस एसएचओ के प्रकाशित किये गये थे। लेकिन कार्यवाही के नाम पर उसका तबादला मात्र ही हुआ और अब उसकी तनाती स्टेट विजिलैंस ब्यूरो में हो चुकी है जहां उसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ना व उनके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करना है। समझा जा सकता है कि ऐसा निकृष्ट इन्स्पेक्टर कैसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ेगा, कैसी जांच करेगा और अपने मातहतों को क्या सिखायेगा। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि विष्णु अभी 4 साल पहले ही सीधे इन्स्पेक्टर के पद पर हुड्डा के राज में भर्ती हुआ था। इस पद पर भर्ती होने वाला प्राय: आई जी के पद तक पहुंचता है। जब विष्णु जैसे अफ़सर होंगे तो महकमे का हाल क्या होगा समझना कठिन नहीं।

कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। परन्तु ऐसी गंदी मछलियों की बहुतायत हो जाय तो तालाब का सड़ना तय है। विष्णु तो इन्स्पेक्टर था, यहां तो डीएसपी व एएसपी स्तर के अधिकारियों को ढाबों व रेस्तराओं से चिकन मांगते या मांगाते अक्सर देखा गया है। बरसों पहले नेहरू ग्राऊंड के एक ढाबा मालिक द्वारा मुफ़्त में चिकन देने से मना करने पर तत्कालीन एसएचओ ने उसके यहां रेड करके उसे फ़ांसने का असफ़ल प्रयास भी किया था। प्रयास असफ़ल इसलिये रहा क्योंकि वह शराब पिलाने जैसा कोई ग़लत काम नहीं करता था मुफ़्त खाने के चक्कर में अक्सर पुलिस खुद ग़लत कामों को बढावा देती है। ग़लत काम न करने वाले होटल वालों को तो पुलिस वाले 'बेकार' ही मानते हैं। इस तरह के माहौल में नये-नये भर्ती होकर आये सिपाही रेहड़ियों से बिरयानी व कचौड़ियां क्यों नहीं मांगेगें?

गतांक की चीर-फ़ाड़

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 1-15 जुलाई 2015 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले जो आलोचनात्मक व विचारशील हैं। कुछ लेखों में तो मोदी सरकार की नीतियों व कार्यशैली का सांगोपांग विश्लेषण किया गया है जो कि राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में भी पढने को नहीं मिलते।

योग के व्यवसायीकरण व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि निर्माण करने के सम्बन्ध में लेख 'आप करें आसन, हम करें शासन-भाइयो और बहनो पांच साल रहेगा मोदी का यही हाल', 'योग दिवस: खूब चली भगवा दुकानें' तथा 'मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योग का सहारा' में सटीक विश्लेषण किया गया है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने व अपनी छवि बनाने के लिये स्वचछता अभियान के बाद योग का सहारा लिया गया है। हालाँकि मोदी ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर सफलता का जश्न मनाया परंतु दिल में वह भी जानते हैं कि जनता में उनकी लोकप्रियता अब गिरावट पर है। योग पद्धति तो प्राचीन काल से है और लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर योग करते भी हैं तथा अनेक ऋषि-मुनि व साधु संत अपने-अपने आश्रम में योग करते हैं।

स्वामी रामदेव ने योग का व्यवसायीकरण किया जबकि रामदेव से भी उच्च कोटि के योगी हैं जो योग करते हैं और योगाभ्यास कराते भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिये अपनी पूरी सरकार, पार्टी व प्रशासन को इस अभियान में झोंक दिया। सरकार और प्रशासन दोनों कई सप्ताह से इस अभियान को सफ़ल बनाने में जुट गए। इस दौरान सरकार का प्रशासन ठप्प हो गया और करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर दिया। यदि इस धन राशि को सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने व सुविधाएं प्रदान करने पर खर्च किया जाता तो आम लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती और उन्हें मरने अथवा प्राइवेट अस्पतालों की लूट का शिकार नहीं होना पड़ता। इसका नवीनतम उदाहरण है कानपुर के एक मरीज़ का। उसके लीवर का ट्रांसप्लांट लखनऊ मेडिकल कॉलेज में होना था जिसके लिये उसके पास पर्याप्त धन राशि नहीं थी। उसकी प्रार्थना पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ धन राशि उपलब्ध तो करा दी, परंतु लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लीवर ट्रांसप्लांट कराने वालों की लम्बी लिस्ट थी और उसका नम्बर आने से पहले ही उसका देहांत हो गया। अमृतसर के एक गांव के किसान को अपने पिता का दिल्ली के प्राइवेट चेरिटेबल अस्पताल में इलाज कराने के लिये अपनी कृषि योग्य ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। स्पष्ट है कि जो धन राशि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रचार अभियानों पर खर्च की जाती है उसे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने व प्राइवेट अस्पतालों के समकक्ष सुविधाएं प्रदान करने पर खर्च करने की आवश्यकता है।

लेख 'खबर दार-नमो-नमो नहीं लमो-लमो' में क्रिकेट जगत में विभिन्न राजनैतिक दलों जैसे भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि के राजनेता, उद्योगपतियों जैसे रूंगटा, डालमिया, श्री निवासन आदि तथा कुछ बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के गठजोड़ का उचित वर्णन किया गया है।

लेख 'नया थानेदार' में नए थानेदार के नाम से नरेन्द्र मोदी पर उचित कटाक्ष किया गया है। संघ परिवार द्वारा गुजरात में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की सफलता के बाद और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के पश्चात् भाजपा व संघ परिवार ने गुजरात मॉडल को देश में अन्य स्थानों पर दोहराने का अभियान शुरू कर रखा है।

उत्तर प्रदेश में मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों के बाद हरियाणा में भी अटाली गांव के अन्दर साम्प्रदायिक आग फ़ैलाई गई जिसके संदर्भ में लेख 'अटाली की आग बुझ नहीं रही, तनाव और बहिष्कार जारी' महत्वपूर्ण है जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी सुरक्षा के लिये गांव छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर जाने को मज़बूर हो गए और जो लोग वहां रह गए उनके साथ बहुसंख्यक वर्ग के कुछ लोग़ों द्वारा भेदभाव करने के आरोप भी हैं। इसके अतिरिक्त अटाली के बाद अब टीकरी ब्राह्मण गांव, हथीन क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी साम्प्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है।

गौरतलब है कि सोशल नेटवर्किंग द्वारा आपत्तिजनक संदेश से साम्प्रदायिक तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। अभी समय है कि स्थिति को विस्फ़ोटक होने से बचाने के लिये शांतिप्रिय व साम्प्रदायिकता विरोधी ताकतें एकजुट होकर साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करें।

टिप्पणी 'कासनी ने हिसाब मांगा तो पत्ता काटा' से स्पष्ट है कि किसी भी सत्तारूढ राजनैतिक दल को कासनी व खेमका जैसे ईमानदार अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती जबकि ऐसे अधिकारी तो सदैव विपक्ष को प्रिय होते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा देश में व्याप्त आपातकाल लगाने की परिस्थितियों के आसार के सम्बन्ध में लेख 'इमरजेंसी और मोदी सरकार' महत्वपूर्ण है। हालाँकि देश में संसदीय शासन प्रणाली की बजाय व्यक्ति विशेष (मोदी) की प्रभुसत्ता व व्यक्ति पूजा पर बल दिया जा रहा है और यदि भाजपा का कोई नेता मोदी का विरोध अथवा उसकी आलोचना करने का प्रयास करता है तो उसे पार्टी में दरकिनार कर दिया जाता है और विपक्षी को 'देशद्रोही' व 'विकास विरोधी' की संज्ञा दी जाती है।

'तुकी-ब-तुर्की' स्तम्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीबजंग व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के बीच जारी जंग व नजीब जंग का केंद्र के इशारे पर चुनी हुई सरकार के कार्यों में रूकावट डालने के प्रयास का उचित विश्लेषण किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च कोटि के तथा प्रेरणादायक व विचारशील है।